www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 224 नागपुर, सोमवार, 10 जुलाई 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

सैन्य बख्तरबंद वाहनों के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को हरी झंडी

नई दिल्ली

रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को 2,400 करोड़ रुपये के एक प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। यह प्रस्ताव सेना के लड़ाकू वाहनों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। इस अपग्रेडेशन (उन्नयन) से बख्तरबंद वाहनों का रात में भी कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सकेगा।

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस परियोजना पर आगे बढ़ने का फैसला रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की एक बैठक में लिया गया है। डीएसी की इस बैठक में 406 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली सेना के लिए कैरियर कमांड पोस्ट व्हीकल खरीद को भी मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। डीएसी रक्षा मंत्रालय के खरीद संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।

सूत्र ने बताया कि बख्तरबंद वाहनों का आधुनिकीकरण रात में उन्हें पूरी तरह संचालित करने में सक्षम करने के अलावा उनके समग्र प्रदर्शन में बढ़ोत्तरी करेगा।

कमांड पोस्ट व्हीकल केंद्रीकृत कमांड सुविधाओं के रूप में कार्य करते हैं, जो सटीक फायरग सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रानिक कमांड और नियंत्रण प्रणाली से लैस होते हैं। तेलंगाना के मेडक स्थित सरकार द्वारा संचालित आर्डिनेंस फैक्ट्री में बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

चीन के सुरक्षा एडवाइजरी मामले को कूटनीतिक स्तर पर सुलझाएगा केंद्र - भाजपा

बेंगलुरु

सिक्किम से लगी सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन ने भारत जाने वाले और वहां रह रहे अपने नागरिकों के एक सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम महादेव ने रविवार को कहा कि मसले को भारत सरकार द्वारा कूटनीतिक स्तर पर संभाला जाएगा।

उन्होंने यहां मीडिया से बातचीत में कहा, सब कुछ सुलझाया जाएगा। इंडिया फाउंडेशन का प्रतिनिधिमंडल चीन जा रहा है। गौरतलब है कि चीनी दूतावास के जरिए नई दिल्ली में एडवाइजरी जारी की गई है। शनिवार को एडवाइजरी के जरिए भारत आने वाले चीनी यात्रियों को सुरक्षा स्थिति पर करीब से नजर बनाए रखने और एहतियात बरतने को कहा गया है।

चीनी विदेश मंत्रालय ने जोर देते हुए कहा है कि यह एक एडवाइजरी है ना कि एलर्ट। हालांकि इनके बीच का अंतर नहीं बताया। चीन की ओर से यह एडवाइजरी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात के एक दिन बाद ही जारी की गई है।

प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और इंटरनेट का लाभ उठाएं छात्र - राष्ट्रपति

नई दिल्ली

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित डिजिटल पहल पर राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वयं, 32 स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों और राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी के शुभारंभ समारोह में भाग लिया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और इंटरनेट के प्रसार ने छात्रों की पहुंच और गुणवत्ता के मामले में खाई को कम करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है और हमें इस अवसर से अपने दोनों हाथों से लाभ उठाना चाहिए। डिजिटल प्रौद्योगिकी अच्छे शिक्षकों को बड़ी संख्या में उन छात्रों तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने में सक्षम बना रही है जो शारीरिक रूप से कक्षाओं में मौजूद नहीं हो पाते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि वे इस बात से काफी प्रसन्न हैं कि स्वयं पोर्टल अब पूरी तरह से कार्यरत हो गया है जिससे छात्र अब कहीं भी रहकर सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा पेश किए गए पाठ्यक्रमों से लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अग्रणी शिक्षक अब एमओओसी फॉर्मेट वाले इस प्लेटफॉर्म पर अपने नए पाठ्यक्रमों को पेश कर सकते हैं।

राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि 32 स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों के जरिए उपग्रह तकनीक की पहुंच कई गुना बढ़ गई है। ये चैनल उन ग्रामीण इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों की मदद करेंगे जहां आईटी बुनियादी ढांचा अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।

राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी से विभिन्न संस्थानों द्वारा जारी किए गए प्रत्यय पत्रों या प्रमाण पत्रों के आसान प्रमाणीकरण में मदद मिलेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कामकाज में सहूलियत भी होगी। इस अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) राज्य मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय भी मौजूद थे।

आदर्श घोटाला: रक्षा मंत्रालय की जांच में दो पूर्व जनरल के नाम आए सामने

नई दिल्ली

मुंबई के आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला मामले में रक्षा मंत्रालय की तरफ से नियुक्त उच्च स्तरीय समिति ने अपनी जांच में सेना के दो पूर्व प्रमुखों जनरल एन सी विज और जनरल दीपक कपूर तथा कई अन्य सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की संलिप्तता पाई है।

जांच समिति ने अपने सौ पन्ने की रिपोर्ट में तीन सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जी एस सिहोता, तेजिंदर सिंह और शांतनु चौधरी तथा चार मेजर जनरल ए आर कुमार, वी एस यादव, टी के कौल और आर के हुड्डा के नामों का भी जिक्र किया है। इसने कई अनियमितताओं का जिक्र किया है।

अपार्टमेंट कारगिल के नायकों के परिजनों के लिए थे

मुंबई में बनाए गए अपार्टमेंट कारगिल के नायकों के परिजनों के लिए थे, लेकिन नियमों का उल्लंघन कर सैन्य अधिकारियों, नेताओं और नौकरशाहों को कथित तौर पर फ्लैटों के आवंटन किए गए। वर्ष 2010 में सामने आने के बाद आदर्श घोटाला भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया और इससे एक बड़ा राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ था। इस घोटाले के कारण महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा था।

जांच के दायरे में आए जमीन पर जनरल विज ने सवाल नहीं उठाए

जांच के मुताबिक प्रतीत होता है कि जनरल विज ने जांच के दायरे में आए जमीन के लिए किसी भी चरण में कोई सवाल नहीं उठाए न ही उन्होंने वार्षिक सुरक्षा समीक्षा के दौरान कोई सुरक्षा चिंता जाहिर की। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चला कि उनका इस मामले में निहित स्वार्थ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरल कपूर भले ही मामले में सीधे जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन सोसायटी की सदस्यता हासिल करने में उन्हें ठीक से सलाह नहीं दी गई। इसमें कहा गया है कि परिसर में फ्लैट लेने के परिणाम पर उन्होंने गहनता से विचार नहीं किए।

भारतीय नौसेना ने सुरक्षा चिंताएं जताई थीं क्योंकि भवन से इसके कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान सीधे नजर आते थे। भवन परिसर का निर्माण रक्षा मंत्रालय की जमीन पर किया गया था और इसमें कारगिल युद्ध के नायकों और युद्ध में अपने परिजनों को गंवाने वालों को लाभ मिलना था। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

सेना को मिलेगी और मजबूती, 1.85 लाख राइफल खरीदेगी सरकार

नई दिल्ली

सरकार सेना के लिए उच्च क्षमता वाली 1.85 लाख राइफल खरीदेगी। ये पुरानी हो रही इंसास राइफलों की जगह लेंगी। सेना द्वारा स्वदेशी असाल्ट राइफल लेने से मना करने पर सरकार ने खरीद प्रक्रिया तेज करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, सेना ने सीमावर्ती इलाकों और आतंक रोधी अभियानों में अपनी

क्षमता बढ़ाने के लिए इच्छापुर राइफल फैक्ट्री में तैयार हो रही गन के लिए दबाव बनाया था। उसने 65 हजार ऐसी राइफलों की तुरंत खरीद की मांग की थी, लेकिन पिछले महीने सेना ने सरकारी राइफल फैक्ट्री की इस गन को खराब गुणवत्ता और फायरिंग में अप्रभावी बताते हुए ठुकरा दिया था। सेना ने पिछले साल भी स्वदेशी राइफल 5.56 एमएम एक्सकैलिबर गन को खारिज कर दिया था।

अमरनाथ यात्रा फिर बहाल, 4411 श्रद्धालु रवाना

जम्मू

अमरनाथ यात्रा एक दिन स्थगित रहने के बाद रविवार को फिर से बहाल हो गई। आधार शिविर यात्री निवास भगवती नगर से 4411 श्रद्धालुओं का जत्था पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना किया गया। जत्थे में 3316 पुरुष, 763 महिलाएं और 332 साधु शामिल थे, जो 43 हल्के वाहनों और 97 बसों में सवार होकर यात्रा पर गए।

दो देशों के दौरे के बाद वापस लौटे पीएम मोदी

नई दिल्ली

अपने दो देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली वापस लौट आए। उन्होंने अपने इस दौरे की शुरुआत इजरायल से की, जहां सात समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने कारोबारी समुदाय से भी मुलाकात की, जहां भारतीय और इजरायली कारोबारियों के सीईओ ने पांच बिलियन डॉलर के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। फोरम ने स्टार्टअप्स, फार्मा, होमलैंड सिक्युरिटी, कृषि, ऊर्जा और जल क्षेत्र से संबंधित छह संयुक्त कमेटी का गठन भी किया। इजरायल के बाद पीएम मोदी -20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी के हैम्बर्ग रवाना हो गए। शुक्रवार को सम्मेलन के पहले दिन पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग समेत कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की।

गोरखालैंड की मांग पर दार्जिलिंग में फिर हिंसा, चार की मौत, सेना तैनात

कोलकाता

गोरखालैंड की मांग पर पहाड़ में चल रहे आंदोलन के कुछ दिन शांत रहने के बाद शनिवार को फिर हिंसा भड़क गई। दार्जिलिंग के सोनादा इलाके में गोरखालैंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) के कार्यकर्ता तांशी भूटिया का शव मिलने के बाद आंदोलनकारी हिंसक हो उठे। उन्होंने कई जगहों पर जमकर उत्पात मचाया। पुलिस फायरिंग में तांशी की मौत का आरोप लगाते हुए उग्र कार्यकर्ताओं ने सोनादा थाना, पुलिस तथा ट्रैफिक पोस्ट व ट्रॉय ट्रेन के स्टेशन पर तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। उन्होंने जगह-जगह पुलिस वाहन में तोड़फोड़ भी की। उग्र प्रदर्शन को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा तथा आंसू गैस के गोले दागने पड़े। सुबह से शाम तक पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच झड़पें होती रहीं। शुक्रवार रात से शनिवार शाम तक हुई हिंसक घटनाओं में चार लोगों की मौत व

आठ लोगों के घायल होने की सूचना है। हिंसा के फिर उग्र होने पर दोबारा सेना की तैनाती की गई है। दार्जिलिंग व सोनादा में 100 जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पहले से तैनात पुलिस व अर्धसैनिक बल स्थिति को नियंत्रित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। शनिवार को सुरक्षाबलों ने शांति कायम करने के लिए फ्लैग मार्च भी किया। घटना के बारे में बताया गया है कि मृतक तांशी भूटिया शुक्रवार देर रात अपने बीमार भाई के लिए दवा लेने जा रहा था। इसी क्रम में सीआरपीएफ की गोली से उसकी मौत हो गई। जीएनएलएफ ने तांशी को अपना कार्यकर्ता बताते हुए पुलिस फायरिंग में उसकी मौत की प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। पुलिस द्वारा इससे इन्कार के बाद कार्यकर्ता उग्र हो गए।

हालांकि बाद में परिजनों, गोजमुमो (गोरखा जनमुक्ति मोर्चा) व अन्य पर्वतीय दलों की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली, जिसमें हत्या का आरोप लगाया गया है। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

राजनाथ ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से की बातचीत, सुरक्षा का दिया आश्वासन

नई दिल्ली

केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज सिक्किम सरकार को प्रदेश की जीवन रेखा राष्ट्रीय राजमार्ग 10 की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में पृथक गोरखालैंड की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शनों और उसके विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के कारण जरूरी चीजों की कमी से जूझ रहा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के साथ फोन पर हुई बातचीत में गृहमंत्री ने राज्य में और पश्चिम बंगाल से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा मामलों पर चर्चा की। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि केन्द्र एनएच-10 की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और राज्य के लोगों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

निजी वाहनों को असामाजिक तत्व बनाते हैं निशाना

सिंह ने केन्द्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को निर्देश दिया कि

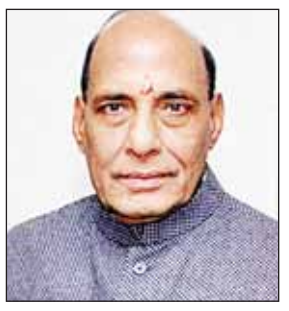

वह पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समन्वय कर एनएच-10 पर यातायात के सुरक्षित और सामान्य संचालन सुनिश्चित करें। राजमार्ग पश्चिम बंगाल में सिलिगुड़ी को सिक्किम की राजधानी गंगटोक से जोड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में पंजीकृत वाहन सिक्किम में चलने बंद हो गए हैं, इसके कारण सिलिगुड़ी और गंगटोक के बीच यातायात प्रभावित हो रहा है। सूचनाएं हैं कि सिक्किम जाने वाली टैक्सियों और निजी वाहनों को सिलिगुड़ी में असामाजिक तत्वों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।

गौचर समेत 7000 बीमारियों का निशुल्क होगा इलाज

नई दिल्ली

गौचर एक ऐसी जन्मजात बीमारी है जिसमें मरीज का लिवर बढ़ जाता है। इसकी सभी दवाइयां विदेशों से मंगानी पड़ती हैं, यही वजह है कि अब से पहले इसके इलाज पर खर्च लाखों में आता था जिसे वहन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी, लेकिन अब यह बात पुरानी हो गई है। इसकी वजह है कि हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद गौचर समेत करीब 7000 बीमारियों का इलाज निशुल्क संभव हो पाया है। इसको लेकर 25 मई 2017 को केंद्र ने कानून बनाते हुए इन बीमारियों से लड़ने के लिए 100 करोड़ का कोष तैयार किया है। इसमें मरीजों के इलाज पर होने वाला 60 फीसद खर्च केंद्र, जबकि 40 फीसद खर्च राज्य सरकार द्वारा गठित कोष से दिया जाएगा।

कुछ ऐसी है टंपे कमेटी रिपोर्ट

गौचर से संबंधित डीके टंपे कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि इस बीमारी के इलाज पर होने वाला खर्च लाख से करोड़ रुपये तक है। इतने पैसे में दस हजार मलेरिया से पीड़ित मरीजों और करीब 400 एचआईवी पीड़ित मरीजों का इलाज किया

जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अभी तक पहचान किए गए रेयर डिजीज में से अमेरिका में हर एक हजार लोगों में से करीब छह लोग इनसे पीड़ित हैं, वहीं जापान में इनकी संख्या प्रति हजार पर चार है। विश्व में करीब छह से आठ हजार रोग रेयर डिजीज कैटेगरी में पहचान में आए हैं, जिनमें से करीब 450 बीमारियों से पीड़ित मरीज भारत में हैं।

निशुल्क इलाज

इस बारे में कोर्ट ने 11 अगस्त 2017 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव को इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी देने का भी आदेश दिया है। इसमें वह बताएंगे कि बिना किसी परेशानी के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मरीज केंद्र द्वारा बनाए कानून का लाभ कैसे ले सकेंगे। अब देशभर में गौचर, फेबरी,पाम्पे, एमपीएस-1 सहित हजारों तरह की बीमारियों का निशुल्क इलाज हो सकेगा। आम तौर पर इन बीमारियों के इलाज में लाखों का खर्च आता है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है।

आसान नहीं थी लड़ाई

केंद्र की इस पहल के पीछे आपको इस बात की भी जानकारी होनी जरूरी है कि आखिर यह सब कैसे संभव हो पाया है। यह सब इतना आसान नहीं था। इस कानूनी लड़ाई में सबसे पहली जीत 17 जनवरी, 2014 को उस वक्त मिली थी जब कोर्ट ने गौचर समेत अन्य आनुवांशिक और दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों के निशुल्क इलाज के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार को नीति बनाने का आदेश दिया था। जिसकी बदौलत यह संभव हो पाया और केंद्र को पहल करनी पड़ी वह कोई बहुत पढ़ा-लिखा या कोई अमीर इंसान नहीं है, बल्कि एक रिक्शा चलाने वाला सिराजुद्दीन है।

रिक्शा चालक है सिराजुद्दीन

दरअसल, सिराजुद्दीन ने अपने पांच बच्चों को इसी बीमारी के चलते खो दिया था। अपने बच्चों की मौत का गम सहने वाले सिराजुद्दीन ने समाज के लिए वो काम कर दिखाया जो कोई पढ़ा-लिखा और अमीर आदमी भी नहीं कर सका, लेकिन सिराजुद्दीन ने सैकड़ों की जिंदगी बचाने की व्यवस्था कर दी है।

जीएसटी के नाम पर कोई करे परेशान तो इस नंबर पर करें कॉल

नई दिल्ली

अनधिकृत टैक्स अधिकारी व्यापारियों की दुकान और प्रतिष्ठानों पर नहीं धमक पाएंगे। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई अधिकारी अनधिकृत तौर पर किसी की दुकान पर पहुंचता है तो हेल्पलाइन (011-23370115) पर कॉल कर उसकी शिकायत की जा सकती है।

वित्त मंत्रालय ने यह कदम उन खबरों के बाद उठाया है, जिनमें कहा गया था कि कुछ लोग खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर दुकानदारों के पास जा रहे हैं। इस बीच, वित्तमंत्री अरुण जेटली ने व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों की मदद के लिए एक मोबाइल एप लॉन्च किया है।

जीएसटी लॉन्च करने के बाद अब केंद्र सरकार आम लोगों और व्यापारियों को इसके बारे में सही जानकारी देने में

लगी है।

इस एप की मदद से लोगों को किसी भी चीज पर लगने वाले जीएसटी की सही जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल यह एप एंड्रायड स्टोर में उपलब्ध है और जल्द ही इसे आईएसओ व विंडोज के लिए भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसे आप एंड्रायड प्ले स्टोर में लिखकर सर्च कर सकते हैं। इस एप को डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही इसे खोलेंगे इसमें आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे। इनमें पहला ऑप्शन टैक्स ऑन गुड्स का है जिसमें शून्य से लेकर 28 प्रतिशत जीएसटी की लिस्ट है। इसमें आप जिस भी कैटेगरी में जाएंगे आपको उन प्रोडक्ट्स की जानकारी मिल जाएगी जिन पर टैक्स लगा है। मसलन आप जानना चाहते हैं कि किन चीजों पर सरकार शून्य प्रतिशत जीएसटी लगाया है तो आप इसमें गुड्स एट जीरे परसेंट पर क्लिक करें और आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी।

ऐसा ही दूसरा ऑप्शन सर्विस टैक्स रेट का दिया गया है। तीसरा ऑप्शन इंफॉर्मेशन का है जिस पर क्लिक करते ही आप जीएसटी वेबसाइट के पेज पर चले जाएंगे जहां और भी जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा इसमें सर्च का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप सीधे चीजों को सर्च कर जीएसटी रेट देख सकते हैं।